भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1927

11 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

जापान से इस्पात का आयात

1927. श्री हैबी ईडन:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को जापान से आयातित इस्पात की खेपों को भारतीय बंदरगाहों पर रोके जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और उक्त शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या आयात पर इस तरह के अंकुश के परिणामस्वरूप देश में इस्पात की कीमतें बढ़ गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी बढ़ी हुई कीमतों से कतिपय बड़ी इस्पात कंपनियों को लाभ हो रहा है और इससे छोटे विनिर्माताओं को हानि हो रही है; और

(घ) मंत्रालय द्वारा उक्त समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क): भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), इस्पात मंत्रालय के परामर्श से यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है कि देश में केवल गुणवत्तापूर्ण इस्पात ही उत्पादित हो अथवा बाहर से आयात किया जाए। इस दिशा में, 151 बीआईएस मानकों को अधिसूचित किया गया है और इनको इस्पात मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतिम उपयोगकर्ताओं और आम जनता को केवल गुणवत्तापूर्ण इस्पात ही उपलब्ध कराया जाता है। बाहर से इस्पात के किसी प्रकार का आयात केवल बीआईएस लाइसेंस के साथ किया जा सकता है। हालांकि, कुछ इस्पात ग्रेड जो अभी तक बीआईएस मानकों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, उनका इस्पात मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) के साथ आयात किया जा सकता है। आगामी छह महीनों के लिए आयात की जाने वाली अपेक्षित मात्रा के आधार पर अग्रिम रूप से एनओसी जारी की जा रही है।

जापानी निर्यातकों से अग्रिम एनओसी के लिए आवेदनों पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार नियमित आधार पर निर्णय लिया जा रहा है।

(ख) से (घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है जहां इस्पात की कीमतें बाजार की गतिशीलता द्वारा निर्धारित होती है और इसकी उपलब्धता के आधार पर उतार-चढ़ाव होती है। सरकार देश में इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित कर, एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है।

*****